an>

Title: Need to allocate funds under PMGSY for the completion of pending work in Hardoi Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

डॉ. अंशुल वर्मा (हरदोई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र हरदोई में वर्ष 2012-13 के पीएमजीएसवाई फेज-10 के 25 मार्गों को पैकेजवार स्वीकृति प्रदान की गयी थी और मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था। ये धन अभाव के कारण आधे-अधूरे पड़े हैं। जिससे क्षेत्रीय कृषकों, व्यापारीगणों, छात्रों एवं जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई होती है। इस संबंध में जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर अधिकारियों को स्वयं के द्वारा पत्राचार किया जा चुका है। फेज-10 के 25 मार्गों के पैकेज में 7662.35 लाख रुपये के सापेक्ष संख्या नम्बर 2243.06 लाख रुपये ही अभी तक मिले हैं। शेष आवंटन 5419.29 लाख रुपये बाकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि शेष आवंटन राशि निर्गत करने की कृपा करें, जिससे अधूरे कार्य पूर्ण हो सकें और क्षेत्रीय जनता के बीच जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़क निर्माण कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ही सांसदगणों के पास है, जिसका सीधा श्रेय भारत के प्रधानमंत्री जी को जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े-बड़े नेता मंचों से एवं समाचार पत्रों के माध्यम से घोषणा करते हैं कि यह सड़क निर्माण कराने की स्वीकृति उन्होंने दी है। यह सड़क जल्दी बनेगी, क्योंकि यह पीएमजीएसवाई की होती है। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार सांसदों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। जैसे उत्तर प्रदेश शासन के विभागो में मंडी परिषद, गन्ना संस्थान, लोहिया समग्र विकास, गांव आदि विभागों के विकास कार्यों में केवल सत्ता के एम.एल.ए. के ही प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं।